20 अरब का कर्ज मिले तो हो गन्ना मूल्य भुगतान

राज्य मुख्यालय| प्रमुख संवाददाता

हिन्दुस्तान P-11, 12-7-13

सरकार से मांग

- गन्ना व चीनी के दाम के बीच सामंजस्य बनाकर तय हो मूल्य : एसोसिएशन
- कर्नाटक व महाराष्ट्र की तर्ज पर यूपी में भी लागू हो रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट

प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने के लिए यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार से दो हजार करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त कर्ज की मांग की है। उसने कहा है कि यह कर्ज या प्रदेश सरकार खुद दे अथवा अपनी गारण्टी पर केन्द्र से दिलवाए। इसके साथ ही एसोसिएशन ने गन्ना मूल्य और बाजार में चीनी की कीमतों के बीच सामंजस्य रखते हुए अगले पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य तय किए जाने का आग्रह भी किया है।

लखनऊ में गुरुवार को यूपी शुगर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारी मीडिया से मुखातिब हुए।

गुरुवार को प्रदेश में चीनी उद्योग के विकास के मसले पर एसोसिएशन के अध्यक्ष सीबी पटौदिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल मुख्य सचिव जावेद उस्मानी से मिला। बाद में प्रेस कांफ्रेंस में एसोसिएशन के महानिदेशक अबिनाश वर्मा ने बताया कि 2012-13 के पेराई सत्र में गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य 280 रुपए प्रति कुन्तल किए जाने से यूपी में एक किलोग्राम चीनी की उत्पादन लागत 35 रुपए पहुंच गई। जबकि बाजार में चीनी की कीमत 31 रुपए किलो के आसपास ही बनी रही। चीनी मिलों को हुए नुकसान के चलते बैंकों ने भी किनारा कर लिया जिसकी वजह से किसानों को गन्ना मूल्य के भुगतान में दिक्कतें बढ़ गईं।

श्री पटौदिया ने उ.प्र. में रंगराजन समिति की रिपोर्ट लागू करने की पुरजोर मांग करते हुए बताया कि कर्नाटक ने इस समिति की रिपोर्ट अपने यहां लागू कर दी है और महाराष्ट्र सरकार भी इसे लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि गन्ने का अधिक मूल्य देना तभी मुमकिन होगा जब ज्यादा परते वाले गन्ने की पैदावार बढ़े। इसके लिए कर्नाटक व महाराष्ट्र की तर्ज पर प्रदेश में भी उन्नत किस्म की प्रजातियों के गन्ने को बढ़ावा दिया जाना जरुरी हो गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 24 जिलों में चीनी मिलें, सह-उत्पाद इकाई स्थापित करने या उसका विस्तार करने पर कई तरह की सहूलियतों के एलान पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक गन्ने व चीनी के दाम के बीच सामंजस्य बनाकर गन्ना मूल्य तय नहीं होगा तब तक राज्य में नई चीनी मिलें नहीं आएंगी।